

सं० ओ० वि० एफ०डी/90-86/30114.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० दी पलवल कोपरेटिव शूगर मिल्ज लि०, पलवल, जिला फरीदाबाद के श्रमिक श्री गंगा राम, पुत्र श्री मलूका राम, गांव व डाकखाना बामनी खेड़ा, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ?

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवाद-ग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं ।

क्या श्री गंगा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी/83-87/30121.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० 1. गुरवचन सिंह एण्ड कम्पनी एस्कोर्ट प्लाट नं० 2, 19/6, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, 2. मैनेजर एस्कोर्ट प्लाट नं० 2, 19/6, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रमेश सिंह विष्ट मार्फत कार्यालय, फरीदाबाद इन्जीनियरिंग मजदूर युनियन जी-162, इन्दरा नगर, सैक्टर 7, फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं ।

क्या श्री रमेश सिंह विष्ट, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/रोहतक/77-87/30129.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० 1. परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ । 2. महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्या परिवहन, रोहतक, के श्रमिक श्री रमेश कुमार हैल्पर, पुत्र श्री देश राज, गांव खीदवाली, जिला रोहतक, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उपसे सुसंगत या उपसे सम्बन्धित नीचे लिखे मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है:—

क्या श्री रमेश कुमार की सेवाओं का समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफ०डी/56-87/30137.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० 1-मनेजिंग डायरेक्टर, कन्फेड, एस० सी० ओ० नं० 1014-15, सैक्टर 22-बी, चण्डीगढ़ । 2-मैनेजर, कन्फेड, प्लाट नं० 94, सैक्टर 6, फरीदाबाद । के श्रमिक श्री देवा सिंह, पुत्र श्री गुरदयाल सिंह गली नं० 3, अमरगढ़ गामड़ी, बैथल, जिला कुश्नौर, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं ।

क्या श्री देवा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?